

की गई है कि राज्य सरकारें निबन्धनों के कुठेर अधिकार संबोध संगठनों का सौंप सकें ; और

- (3) यह एक सामान्य नीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि ज्यों सरकार समिति की प्रशंसा में भाग लेती है, व्यों सरकार को अधिक से अधिक तीन निदेशक प्रथवा निदेशकों को कुल संख्या का 1/3, जो भी कम हो, मनोनित करने चाहिए और ऐसे मनोनित निदेशकों को रोध-अधिकार (वोट) नहीं होना चाहिए ।

#### Relief works in famine areas

5727. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation be pleased to state:

(a) the progress made for introducing special works programme under the Famine Code in the drought affected areas; and

(b) the allocations made for creating permanent assets to provide employment to the people in these areas?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) According to the information available with the Central Government, the number of relief works started in the various drought affected States and the number of persons working on these works are as follows:—

Name of State	Number of relief works	Number of persons on relief works
Madhya Pradesh	3,153	8,29,300
Maharashtra	5,862	5,64,897
Orissa	19,600	3,30,000
Mysore	2,103	1,49,372
Karnataka	1,151	2,10,770
Gujarat	503	2,00,000
Andhra Pradesh	3,334	97,701

(b) No separate allocations have been made for creating permanent assets, but the State Governments have been asked to undertake advance execution of plan schemes by way of relief works so that permanent assets are created.

#### Jayanti Shipping Company

5728. Shri P. C. Borooah:  
Shri Hari Vishnu Kamath:  
Shri S. M. Banerjee:  
Shri Daji:

Will the Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jayanti Shipping Company has requested Government for a loan of Rs. three crores urgently, while inquiry into the allegations of mismanagement against the company are still in progress;

(b) if so, the purpose for which the loan has been sought; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) No, Sir. A request for a loan of only Rs. 1.5 crore was received and this was subsequently withdrawn.

(b) and (c). Do not arise.

#### Cochin Port

5729. Shri Daji:  
Shri Warior:

Will the Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a floating crane bought from Holland

for use at Cochin Port is lying unused for the last six months;

(b) If so, the reasons therefor;

(c) the total cost of the crane; and

(d) the steps taken to ensure early use of the crane?

**The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy):** (a) Yes. The floating crane ordered on Messrs. Hensen's of Rotterdam arrived at Cochin Port in December, 1965.

(b) There were certain defects in regard to generator and power output. The speed in water was lower than the speed specified in the contract.

(c) The total cost of the crane is Rs. 68 lakhs including Customs duty of Rs. 21.5 lakhs.

(d) The defects in generator and power output were set right in March. As regards rated speed, the matter is under discussion between the Port Trust and the manufacturing firm. As this defect does not affect operations, the Port Trust are endeavouring to bring the crane into use, subject to legal safeguards, pending arrangements for sending the vessel to Bombay and dry docking it for examination of the hull.

#### घालू का निर्यात

5730. श्री हुकूम खन्ड कछराय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश से श्रीलंका तथा मध्य पूर्व के देशों को घालू निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों से घालू के अच्छे बीजों का आयात करने का है ; और

(घ) इस वर्ष उत्तर प्रदेश में कितना घालू पैदा हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उल-मंत्री (श्री इय्याम्बर मिश्र): (क) और (ख). अन्य जिनसों की भान्ति घालूओं के निर्यात के झांकड़े प्रखिल भारतीय प्राधार पर रखे जाते हैं न कि राज्यों के प्राधार पर। धत : यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी प्रवधि में केवल उत्तर प्रदेश से कितने मूल्य का तथा कितना घालू निर्यात किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उत्तर प्रदेश में 1965-66 के मौसम के लिये घालू के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

#### राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं

5731. श्री हुकूम खन्ड कछराय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये शाखायें किन किन जिलों में खोली जायेंगी और उनसे जनता को क्या लाभ होगा ;

(ग) इनमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का क्रमशः कितना कितना प्रतिशत हिस्सा होगा ; और

(घ) अन्य राज्यों में इस प्रकार की कितनी शाखाएं हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेहन): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य